दाल, एडिबल ऑयल के इंपोर्ट के बदले शुगर एक्सपोर्ट का प्लान!

[पीटीआई | नई दिल्ली]

शुगर सेक्टर को संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार कई विकल्पों पर विचार कर रही है। इनमें फार्म इंपोर्ट्स के बदले शुगर के एक्सपोर्ट का उपाय भी शामिल है। इससे चीनी मिलों को अपना सरप्लस स्टॉक निकालने में मदद मिलेगी और वे गन्ना किसानों का बकाया पैसा चुका पाएंगी।

पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग में शुगर इंडस्ट्री के क्राइसिस पर चर्चा की थी। इस क्राइसिस के चलते किसानों का मिलों पर बकाया 14,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। मोदी ने संबंधित मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे शुगर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें और पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाएं। सूत्रों के मुताबिक, 'फूड मिनिस्ट्री कई ऑप्शंस पर काम कर रही है। इनमें शुगर के लिए एक्सपोर्ट लाइन खोलना भी शामिल है। मिनिस्ट्री ऐसे देशों के साथ बार्टर सिस्टम के तहत शुगर एक्सपोर्ट को मंजूरी देने पर भी विचार कर रही है, जिनसे इंडिया एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का इंपोर्ट करता है।' इंडिया एडिबल ऑयल्स का बड़े पैमाने पर इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट करता है। साथ ही कनाडा, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया से दालों की खरीदारी करता है। मिनिस्ट्री इस बात की भी संभावना तलाश रही है कि क्या शुगर मिलों को चीनी के टोटल एनुअल प्रॉडक्शन के एक निश्चित हिस्से को एक्सपोर्ट करने को अनिवार्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा शुगर सेल पर मौजूदा 24 पैसे प्रति किलो की दर से लगने वाले सेस को बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है ताकि डोमेस्टिक मार्केट में कीमतों में गिरावट को रोका जा सके।

निकलेगा सरप्लस स्टॉक

- **सरकार के** इस प्लान से चीनी मिलों को अपना सरप्लस स्टॉक निकालने में मदद मिलेगी और वे गन्ना किसानों का बकाया पैसा चुका पाएंगी
- **शुगर इंडस्ट्री** के क्राइसिस के चलते किसानों का मिलों पर बकाया 14,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है

मौजूदा कीमत पर शुगर को इंटरनेशनल मार्केट में बेचने से फायदा नहीं होगा क्योंकि वहां इसकी सप्लाई अधिक है। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की कीमत 6 साल में सबसे कम हो गई है। ऐसे में मिनिस्ट्री से 40 लाख टन सरप्लस शुगर के एक्सपोर्ट के रास्ते तलाशने के लिए कहा गया है।

इसके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है, लेकिन अंतिम फैसला एक और राउंड की मीटिंग के बाद ही होगा। सूत्रों के मुताबिक, मोदी जल्द ही यह मीटिंग बुला सकते हैं। कैश की भारी कमी से जूझ रही शुगर मिलों के लिए किसानों के 14,398 करोड़ रुपये के एरियर का भुगतान करना नामुमकिन हो गया है। शुगर के सरप्लस प्रॉडक्शन से इसकी कीमतें नीचे चली गई हैं। शुगर का एक्स-मिल दाम 20 रुपये प्रति किलो से भी नीचे पहुंच गया है, जबकि प्रॉडक्शन कॉस्ट 30 रुपये प्रति किलो है। देश में अभी भी 1 करोड़ टन का सरप्लस स्टॉक बना हुआ है।